भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 154
22.07.2024 को उत्तर के लिए

केरल में पर्यावरण संवेदनशीलता

154 श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य के पर्यावरण संबंधी अवक्रमण और संवेदनशीलता के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है जिसके परिणामस्वरूप अचानक आई बाढ़ होती रहती है तथा भू-स्खलन होता रहता है और ऊपरी मिट्टी में गाद जमा हो जाती है जिससे मृदा की सुभेद्यता बढ़ जाती है और यह संवेदनशील हो जाती हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में व्याप्त पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को राज्य में कुट्टानाड तालुक के कई भागों में जल भराव में वृद्धि की जानकारी है जिससे कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र बेकार हो गए हैं;
(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे का समाधान करने में राज्य की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
(ङ) जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षति और आजीविका के नुकसान के प्रबंधन के लिए आज तक आवंटित धनराशि, यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल राज्य के पर्यावरण के पर्यावरणीय अवक्रमण और भंगुरता के संबंध में कोई विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लगातार बाढ़, भूस्खलन और ऊपरी मिट्टी में गाद जमा होने से मृदा की भेद्यता बढ़ जाती है और यह भंगुर भी हो जाती है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना 2023-2030 (एसएपीसीसी 2023-2030) के एक हिस्से के रूप में, राज्य के लिए समग्र जलवायु परिवर्तन भेद्यता प्रोफाइल तैयार किए गए थे और प्रणालीगत तैयारियों को मापने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों का आकलन भी किया गया था।

(ख) जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के प्रतिक्रिया में, एसएपीसीसी 2023-2030 में केरल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और आपदा जोखिम में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की परिकल्पना की है। इन प्रयासों में वनीकरण

परियोजनाएं, वाटरशेड प्रबंधन, मृदा अपरदन को कम करने और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं। इस योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यनीतियों पर केन्द्रित व्यापक हस्तक्षेपों की परिकल्पना की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की प्रतिरोधकता को बढ़ाना और विस्तृत अध्ययन के आधार पर आपदा प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार करना है।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार कुट्टानाड तालुक में जल भराव की समस्या से अवगत है और सिंचाई, कृषि आदि जैसे राज्य के विभागों द्वारा इसका समाधान किया जा रहा है।

(ङ) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी) के अंतर्गत 25 करोड़ रु की स्वीकृत राशि से केरल की तटीय आद्रभूमियों में कैपाड और पोक्कली की एकीकृत कृषि प्रणाली का संवर्धन नामक एक परियोजना कार्यान्वित की गई थी। इस परियोजना को एक्वाकल्चर विकास एजेंसी, केरल (एडीएके) द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसमें नाबार्ड राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनआईई) है। यह परियोजना 31 दिसंबर, 2015 को शुरू की गई थी और 21 अक्टूबर 2021 तक पूरी हो गई थी। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने राज्य योजना स्कीम 'जलवायु परिवर्तन' के अंतर्गत " कुट्टानाड में जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और ग्रामीण कृषक समुदाय: आपदा प्रबंधन के बजाय आपदा से निपटने के लिए तैयारी" नामक एक परियोजना को 3 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी है जिसका परिव्यय 17.17 लाख रुपये रखा गया है।